राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2015–2016

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	एक परिचय	1
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2
3.	वर्ष 2015–16 की उपलब्धियां	3–5
4.	अभाव स्थिति	5
5.	मानसून की स्थिति	5–6
6.	ओलावृष्टि की स्थिति	6
7.	पशु संरक्षण गतिविधियाँ	7
8.	असहाय सहायता	7
9.	नेपाल में आये भूकम्प से पीड़ितों को सहायता	7
10.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	7–8
11.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	9
12.	राजस्थान राहत कोष	9
13.	राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	10

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	11
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	12
3.	स्वीकृत पदों की स्थिति	13
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	14
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	15
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	16
7.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि अन्तर्गत बजट प्रावधान व व्यय	17
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	18
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	19
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	20
11.	अभाव की स्थिति	21–22
12.	वर्षा की स्थिति	23
13.	सूखा आवृत्ति क्षेत्र का मानचित्र	24
14.	भूकम्प सम्भावित क्षेत्र का मानचित्र	25
15.	सहायता के मापदण्ड	26–36

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एक परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। राज्य के थार मरूस्थल के अन्तर्गत 12 जिलों का 60 प्रतिशत भू–भाग आता है जिसमें राज्य की लगभग 40 प्रतिशत जनता निवास करती है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2012–13 के समंकों के अनुसार प्रदेश में कुल बोये गये 23,954 हजार हैक्टेयर भूमि में से 9,455 हजार हैक्टेयर ही सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 72.83 लाख हेक्टेयर (97.12 प्रतिशत) भूमि कुओं, ट्यूबवेलों तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य की लगभग 75 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर रहती है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2002 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.03 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया हैं।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है, जो शासन सचिव एवं आयुक्त, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता के अधीन कार्य करता है। इस विभाग का मुख्यालय राज्य स्तरीय है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा **परिशिष्ट–1,** विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2,** विभाग में स्वीकृत पदों की स्थिति **परिशिष्ट–3** पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

वर्ष 2015–2016 (दिसम्बर, 2015 तक) की उपलब्धियाँ

1. वर्ष 2015–16 में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2015, 08.10.2015 एवं 22.12.2015 को राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

   दिनांक 01.07.2015 को आयोजित बैठक में खरीफ फसल 2014 (सवंत 2071) में अभावग्रस्त 13 जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित अनुग्रह सहायता की अवधि 30 दिवस से 60 दिवस एवं अधिकतम 90 दिवस किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में एस.डी.आर.एफ. मद से किये गये व्यय का अनुमोदन किया गया।

   दिनांक 08.10.2015 को आयोजित बैठक में अभाव संवत 2071 (वर्ष 2014–15) में 90 दिवस से अधिक अवधि की राहत गतिविधियों पर आवंटित राशि का अनुमोदन किया गया, अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एव नहरों की तात्कालिक मरम्मत हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में से विभाग द्वारा स्वीकृत किए गये प्रस्तावों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया तथा आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक किश्त की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

   दिनांक 22.12.2015 को आयोजित बैठक में रहवासी मकानों में क्षति होने की स्थिति में वर्षा की मात्रा को आधार नहीं लिया जाकर अत्यधिक वर्षा/जल भराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो जाने एवं क्षति संबंधी तथ्यों के सत्यापन का मैकेनिज्म सुनिश्चित कर जिला कलक्टर द्वारा क्षति के आपदा जनित परिस्थितियों में होना निर्धारित कर ही सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया, भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के सुदृढ़ीकरण की योजना को राज्य के 13 जिलों में जनवरी, 2016 से लागू करने हेतु भारत सरकार से एम.ओ.यू. किये जाने का अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष (मुख्यमंत्री महोदया), राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा खरीफ फसल 2015 (संवत 2072) में गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराबा होने पर 19 जिलों के 14487 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किये जाने के पश्चात जारी की गयी विभागीय अधिसूचना का अनुमोदन किया गया एवं संवत 2072 में राहत गतिविधियों के अन्तर्गत गौशाला, पशु शिविरों, सड़कों एवं नहरों आदि के जिलों से प्रस्ताव ऑन लाईन प्राप्त करने एवं विभाग द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों को भी ऑन लाईन ही जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं मे जलने, डूबने तथा मकान ढहने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।

3. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 लागू होने के उपरान्त यह आवश्यक हो गया है कि राज्य आपदा प्रबन्धन नीति में आवश्यक संशोधन समाहित किये जायें एवं अधिनियम के

प्रावधानों के अनुरूप नीति का निर्धारण किया जाये। अतः अधिनियम की धारा 18 की पालना में संशोधित आपदा प्रबन्धन नीति तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।

4. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 23 की अनुपालना में भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।

5. अनुच्छेद 31 की अनुपालना में अधिकांश जिलों की जिला आपदा प्रबन्धन योजनाये तैयार की जा चुकी है , जिनको समय –समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

6. आपदाओं के प्रबन्धन में संसाधनों व जन शक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) वेब साइट के माध्यम से समय–समय पर जिलों द्वारा अद्यतन की जा रही है।

7. भारत सरकार को आपदा प्रबन्धन की वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवा दी गई है।

8. वर्ष 2015 में ओलावृष्टि से प्रभावित 31 जिलों यथा अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, स0माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर में रबी फसलों में 33 प्रतिशत या उससे अधिक खराबा होने पर 29.24 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया। सम्वत 2071 के अन्तर्गत दिसम्बर 2015 तक रबी फसल खराबे पर प्रभावित कृषकों के खातों में कृषि आदान अनुदान सहायता की राशि 2471 करोड़ रूपये हस्तानान्तरण की जा चुकी है।

9. फसल रबी 2015 (2071) में काश्तकारों की बोयी गयी फसलों में माह फरवरी से अप्रेल, 2015 के बीच राज्य में हुई भीषण ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान होने पर राज्य सरकार ने प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु पैकेज जारी किया है। रबी फसलों में 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान होने पर जिला कलक्टरों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 29 जिलों के 8322 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर गतिविधियों का संचालन किया गया है।

10. सम्वत 2071 में सूखा प्रभावित 13 जिलों यथा अजमेर, बांसवाड़ा, बाडमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर एवं प्रतापगढ़ मे काश्तकारों द्वारा बोयी गयी खरीफ फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर 5841 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित कर प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई है एवं प्रभावित जिलों में राहत गतिविधियों का संचालन कर राहत प्रदान की गई है।

11. विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्रम में जिला व राज्य स्तर के मध्य पत्राचार व बजट आवंटन की प्रक्रिया सरल व त्वरित करने की दृष्टि से एक वेब आधारित कम्प्यूटर एप्लीकेशन राजकॉम्प के माध्यम से तैयार करवायी गई है। इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से जिलों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु मदवार ऑनलाइन डिमाण्ड की जाती है जिसकी विभाग संवीक्षा कर आगामी दो दिवस में ऑनलाइन बजट आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, आवंटन–व्यय पर नियन्त्रण, एसी–डीसी बिलों की प्रगति आदि की सूचना भी इसी वैब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इस वेब एप्लीकेशन को और अत्यधिक सूचनावर्धक व उपयोगी बनाने हेतु समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। IFMS के साथ इसका Integration भी किया जा चुका है।

अभाव स्थिति

विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10908–44 दिनांक 19.10.2014, 11279–98 दिनांक 5.11. 2014 एवं 12413–32 दिनांक 12.12.2014 द्वारा सम्वत 2071 में राज्य के 13 जिलों के 5841 गांवों को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

मानसून 2015

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 24.06.2015 को प्रवेश किया एवं दिनांक 26.06.2015 को मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया तथा सामान्य गति से आगे बढते हुये दिनांक 18.08.2015 तक राज्य के सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय रहा एवं अच्छी वर्षा रही। कुल मिलाकर राज्य में 1 जून 2015 से 18 अगस्त 2015 तक की सामान्य वर्षा 371.28 मि.मी. के विरूद्व 477.49 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 28.61 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि से आगे दिनांक 19.08.2015 से 30.09.2015 तक मानसून अप्रत्याशित रूप से असक्रिय हो गया। राज्य में इस अवधि में 158.8 मि.मी. औसत वर्षा होनी थी, इसके मुकाबले में राज्य में मात्र 27.67 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो की सामान्य से (–) 82.58 प्रतिशत कम थी।

01 जून 2015 से 30 सितम्बर 2015 तक राज्य की औसत सामान्य वर्षा 530.08 मि.मी. के विरुद्ध 505.15 मि.मी. दर्ज हुई है, जो कि सामान्य से (–) 4.70 प्रतिशत कम है। मानसून सत्र में 1 जून, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः–

क्र.सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्यवर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर	3
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, झालावाड़	5
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, अजमेर, नागौर, टोंक, झुंझुनू, सीकर, कोटा, बारां, बून्दी, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, राजसमन्द	16
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, प्रतापगढ़	9
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)	कोई नही	0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2015 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11787.612 Mcum की तुलना में 8449.541 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 71.68 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 889.020 Mcum की तुलना में 380.006 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 42.74 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 69.65 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2015 को भरा हुआ था।

मानूसन सत्र 2015 में राज्य में हुई वर्षा तथा गत 2 वर्षो से इसकी तुलना का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–12** पर उपलब्ध है।

ओलावृष्टि

राज्य में वर्ष 2015 में राज्य के 31 जिले यथा अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, क्षतिग्रस्त मकानों एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार अन्य सहायता उपलब्ध करवाई गयी।

पशु संरक्षण गतिविधिया –

संवत 2071 में अभावग्रस्त जिलों की 1,091 पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान प्रदान किया गया, जिसमें 4,53,998 पशु लाभान्वित हुए। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में अभाव संवत 2071 में 3,336 पशु शिविरों में 5,67,469 पशु लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त पशु पालको को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने हेतु 180 चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

असहाय सहायता

इसके अन्तर्गत प्रभावित जिलों के वृद्ध, असहाय एवं निराश्रित बच्चों को आधारभूत सुविधाओं हेतु असहाय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस वर्ष प्रभावित व्यक्तियों को दिनांक 15.7.2015 तक असहाय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

नेपाल में आये भूकम्प से पीड़ितों को सहायता

दिनांक 25.4.2015 को नेपाल में आये भूकम्प के झटके राज्य के कुछ जिलों में महसूस किये गये । भूकम्प के संबंध में सूचनाऐ प्राप्त करने एवं भिजवाने हेतु राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम 24 घन्टे संचालित किया गया।

भूकम्प पीड़ितों को सहायता हेतु राज्य से दो दल दिनांक 26.4.2015 को प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को गोरखपुर/महाराज गंज एवं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में काठमाण्डू भिजवाये गये।

दल के द्वारा 496 व्यक्तियों को अपने गन्तव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने में सहायता की गई । राज्य सरकार द्वारा 47 ट्रकों में राहत सामग्री भिजवाई गई ।

अतिवृष्टि/बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव के कार्य

1. राज्य में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति होने पर जिला झालावाड में 120 व्यक्तियों, जालौर में 495 व्यक्तियों एवं 2 रेलगाडियों में फंसे हुये 500 व्यक्तियों, सीकर में 02 व्यक्तियों, बारां में 30 व्यक्तियों एवं पाली में 03 व्यक्तियो को एस.डी.आर. एफ. एवं एन.डी.आर.एफ. तथा विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराये गये हेलीकॉप्टर , बोट आदि की सहायता से सुरक्षित निकाला गया तथा राहत शिविर लगाये गये जिनमें 23,250 भोजन पैकेट्स व 70 क्विंटल गेंहू वितरण किये गये।
2. बाढ़ में तत्काल बचाव एवं राहत हेतु एस.डी.आर.एफ. एवं एन.डी.आर.एफ को निम्न प्रकार से तैनात किया गया :–

एन.डी.आर.एफ –

i. एन.डी.आर.एफ – 3 टीम 120 कार्मिक 15 बोट – जिला जालौर

ii. एन.डी.आर.एफ.– 2 टीम में से 01 टीम जयपुर संभाग में तैनात की गई है।

iii. एन.डी.आर.एफ. – 1 टीम जिसमें 02 अधिकारी एवं 40 जवान – जिला पाली

iv. एन.डी.आर.एफ. – 1 टीम जिसमें 02 अधिकारी एवं 40 जवान – जिला सिरोही

v. एन.डी.आर.एफ. – 1 टीम जिसमें 02 अधिकारी एवं 40 जवान – जिला बाड़मेर

एस.डी.आर.एफ –

i. आयुक्तालय, जयपुर– 89, आयुक्तालय, जोधपुर– 39, रेंज भरतपुर– 90, रेंज उदयपुर– 80, रेंज बीकानेर– 48, रेंज अजमेर– 37, रेंज कोटा– 102, जिला पाली– 47 एवं जिला जोधपुर ग्रामीण– 39

ii. बाढ़ राहत बचाव कार्य हेतु First Responder कोटा शहर– 20, बारां– 10, झालावाड़– 10, जयपुर आयुक्तालय– 20, डेमा प्लाटून आरपीटीसी जोधपुर– 28 एवं कोटा ग्रामीण – 09

iii. सेना– 61 वीं सब एरिया, जयपुर, जोधपुर सब एरिया, कोटा ब्रिगेड इत्यादि को अलर्ट किया गया ।

3. मानसून वर्ष 2015 में राज्य के 12 जिलों यथा जालोर, बाड़मेर, बारां नागौर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, सीकर, डूंगरपुर, बासंवाड़ा, पाली एवं उदयपुर में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़को की तात्कालिक मरम्मत हेतु जनवरी 2016 तक 2058 कार्यो के लिये 7590.47 लाख रूपये के प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी की गई। राज्य के 9 जिलों यथा जालोर, बाड़मेर, बारां, टोंक जैसलमेर, चित्तौडगढ़, पाली, उदयपुर एवं बांसवाड़ा में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए बांधों/नहरों/विद्यालयो की तात्कालिक मरम्मत हेतु जनवरी 2016 तक 631 कार्यो के लिये राशि 3678.44 लाख रूपये के प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी की गई।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलक्टरों को स्थायी निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे इसके लिए राज्य सरकार से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (माह दिसम्बर 2015 तक) में क्रमशः 560.04 लाख एवं 500.50 लाख रुपये की राशि अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु जिलों को उपलब्ध करवाई गई।

राजस्थान राहत कोष

एस.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबंधन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस कोष में दिये गये अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में छूट का प्रावधान दिनांक 31.3.2018 तक किया गया है।

दिनांक 06.07.2010 को राजस्थान राहत कोष की राज्य स्तरीय समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राजस्थान राहत कोष की आय नाममात्र की रह जाने के कारण इस कोष में प्रतिवर्ष 25.00 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान करवाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव बजट निर्णायक समिति में शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट प्रावधानों (B.E.) में 25.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में रूपये 5.46 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रूपये 1.76 लाख राशि जिलों को बचाव/राहत कार्यों हेतु उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2012–13 के लिये अंकेक्षण पर रूपये 7,416/– एवं वर्ष 2013–14 के लिये अंकेक्षण पर 7,416/– रूपये तथा वर्ष 2014–15 के लिये अंकेक्षण पर 7,524/– रूपये व्यय किया गया।

वर्तमान में इस कोष में बचाव कार्यों हेतु रूपये 4.93 करोड़ की धन राशि उपलब्ध है।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात पूर्व की भाँति ही 3 : 1 रखा है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
योग	2866.02	955.32	3821.34

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये मूल बजट प्रावधान मद 2245–01 सूखा व 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिये 1103.00 करोड़ रुपये स्वीकृत है।

वर्ष 2011–12 से 2015–2016 के अन्तर्गत आपदा राहत कोष/राज्य आपदा मोचन निधि की स्थिति **परिशिष्ट 7** पर एवं इस कोष के अन्तर्गत **अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि** का विवरण **परिशिष्ट 8 व परिशिष्ट 9** पर उपलब्ध है।

सहायता के मापदण्ड

प्राकृतिक आपदा के समय दिये जाने वाले सहायता मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट–15 अनुसार है।

Administrative Set-up

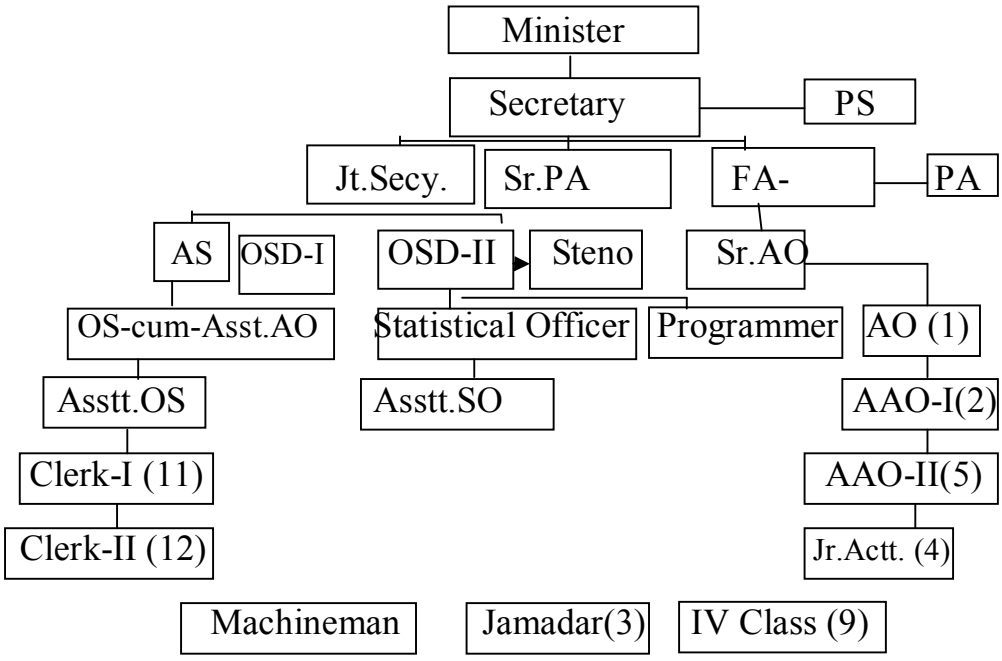

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1.	शासन सचिव	श्री रोहित कुमार	29.12.2014
2.	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	–
3.	शासन उप सचिव	श्री अनिल कुमार पालीवाल	30.09.2015
4.	वित्तीय सलाहकार	श्री अपूर्व जोशी	01.08.2015
5.	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	श्रीमती ममता राव	03.03.2014
6.	विशेषाधिकारी (2)	श्री देशराज मीणा	28.04.2015
		श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	रिक्त	
8.	लेखाधिकारी	रिक्त	
9.	सांख्यिकी अधिकारी	श्री राकेश चन्द्र भार्गव	27.10.2014
10.	सहायक लेखाधिकारी (2)	श्री हीरा लाल शर्मा	10.04.2012
		रिक्त	
11.	प्रोग्रामर	श्री मुकेश कुमार वर्मा	28.03.1994

परिशिष्ट–3

स्वीकृत पदों की स्थिति

क्र.स.	पद नाम	पदों की संख्या	रनिंग पे–बैण्ड	पे–बेन्ड	ग्रेड–पे
1.	शासन सचिव	1	37400–67000	IAS PB 4	10000
2.	विशिष्ठ शासन सचिव	1	37400–67000	IAS PB 4	10000
3.	शासन संयुक्त सचिव	1	37400–67000	PB 4	8700
4.	वित्तीय सलाहकार	1	37400–67000	PB 4	8700
5.	सहायक आयुक्त एवं पदेन शासन सहायक सचिव	1	15600–39100	PB 3	6600
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	15600–39100	PB 3	6600
7.	लेखाधिकारी	1	15600–39100	PB 3	5400
8.	विशेषाधिकारी	2	15600–39100	PB 3	6600
9.	निजी सचिव	1	15600–39100	PB 3	6600
10.	प्रोग्रामर	1	15600–39100	PB 3	5400
11.	सांख्यिकी अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4800
12.	सहायक लेखाधिकारी	2	9300–34800	PB 2	4800
13.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4200
14.	कार्यालय अधीक्षक	1	9300–34800	PB 2	4200
15.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	2	9300–34800	PB 2	3600
16.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	32	9300–34800	PB 2	4200
17.	कनिष्ठ लेखाकार	4	9300–34800	PB 2	3600
18.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	9300–34800	PB2	5400
19.	निजी सहायक	1	9300–34800	PB 2	4200
20.	शीघ्र लिपिक	2	9300–34800	PB 2	3600
21.	लिपिक ग्रेड I	42	5200–20200	PB 1	2800
22.	लिपिक ग्रेड II	20	5200–20200	PB 1	2400
23.	मशीन मैन	1	5200–20200	PB 1	1750
24.	जमादार	3	5200–20200	PB 1	1900
25.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	5200–20200	PB 1	1700

परिशिष्ट–4

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री	सदस्य
3.	गृह मंत्री	सदस्य
4.	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
7.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री	सदस्य
8.	कृषि तथा पशुपालन मंत्री	सदस्य
9.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री	सदस्य

नोट :

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
4. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

परिशिष्ट–5

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

नोट : राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

परिशिष्ट–6

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

प्राधिकरण के निम्नलिखित, स्थाई आमंत्रित होंगे :–

1. जिले के निर्वाचित संसद सदस्य, लोक सभा
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट (सहायता अनुभाग का भारसाधक अधिकारी) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

परिशिष्ट–7

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	SDRF/NDRF 2011-12	SDRF/NDRF 2012-13	SDRF/NDRF 2013-14	SDRF/NDRF 2014-15	SDRF/NDRF 2015-16 (Upto 31-12-2015)
(A) CRF/SDRF					
Opening Balance	4.64	570.20	1141.99	999.22	288.02
Central Share	473.02	496.67	521.50	547.58	827.25
State Share	157.67	165.55	173.83	182.52	275.75
Receipt from Interest	24.60	65.47	75.02	59.67	-
Received from GOI	-	-	-	-	1378.13
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	101.90	0.53	-	-
Total Funds Available under CRF	659.93	1399.79	1912.87	1788.99	2769.15
Expenditure	**89.73**	**257.80**	**913.65**	**1570.57**	**2624.01***
Closing Balance	**570.20**	**1141.99**	**999.22**	**218.42**	**145.14**
(B) NCCF/NDRF					
Opening Balance	69.60	69.60	69.60	69.60	-
Receipts	-	-	-	-	-
Total Fund Available under NCCF	69.60	69.60	69.60	69.60	-
Allotment Made	-	-	-	-	-
Closing Balance	69.60	69.60	69.60	69.60	-
Total Funds available Under SDRF& NDRF(A+B)	**639.80**	**1,211.59**	**1,068.82**	**288.02**	**145.14**

* Amount of Allotment

परिशिष्ट–8

वर्ष 2013–2014, वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

गतिविधि का विवरण	2013–2014	2014–15	2015–16 (31–12–2015 तक आवंटित राशि)
1. अनुग्रह सहायता	332.83	266.40	-
2. पीने के पानी की आपूर्ति	552.28	969.23	1140.79
3. चारा परिवहन	246.22	52.28	566.82
4. पशु पोषण केन्द्र	640.53	-	-
5.पशु शिविर / गौशाला	2182.52	14656.90	21918.74
6. पशु चिकित्सा	(-) 0.01	-	-
7 दवाओं की पूर्ति	-	-	-
8. अन्य विशेष राहत कार्य	(-) 0.24	(-) 1.20	-
9. अग्नि सहायता	453.77	560.04	500.50
10.सर्च एवं रेस्क्यू एव प्रशिक्षण	34.56	576.86	8.53
11.कृषि आदान अनुदान	78262.15	60585.87	7264.24
12.अन्य सहायता	(-) 3.69	-	-
योग	**82,700.92**	**77,666.38**	**31399.62**

परिशिष्ट–9

वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष		
		2013–14	2014–15	2015–16 (31.12.2015 तक आवंटित राशि)
1.	आनुग्रहिक राहत	2.14	-	193.55
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	--	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	1104.51	1492.12	5063.28
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	445.61	248.07	390.07
7.	प्रशिक्षण	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	-
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	26.27	44.62	-
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	54.09	-	299.05
11.	घरों की मरम्मत	646.34	1427.53	3395.95
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	5,928.08	74539.79	220623.07
13.	डिसिल्टिंग	-	-	607.35
14.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	1.10	49.25	333.42
15.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	456.68	1589.12	95.23
16.	नगर निगम को सहायता	-	-	-
17.	नगर पालिका / परिषदों को सहायता	-	-	-
18.	पंचायत समिति / जिला परिषदों को सहायता	-	-	-
19.	मानवीय दवाइयों की आपूर्ति	-	-	-
20.	परिचालन लागत	-	-	-
21.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	-	-	-
22.	अन्य सहायता (कृषि आदान अनुदान)	-	-	-
	योग	**8,664.82**	**7,9390.50**	**231000.97**

परिशिष्ट–10

List of Nodal Departments

S.No.	**Name of Nodal Department**	**Related Disaster**
1.	Disaster management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave, Thunder & Lightening, Cyclones,
2.	Energy	Disasters involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical Biological & Meteorological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Flood and Drainage Management, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines	Mine Fire and Mine Flooding
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires Oil Spill
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack, Frost & Cold Wave
13.	Animal Husbandry	Cattle Epidemics

EXTENT OF SCARCITY (Kharif)

SAMVAT 2071

S.No.	District	Total Villages	No. of Affected villages (50% or more than 50%)	Population Affected (Lac)	Area of Affected Villages			Affected Villages			Value of Damaged Crop (Lac Rs.)	Land Rev. of Affected Villages (Lac Rs.)	likely Suspended of land Rev. (Lac Rs.)	Total Cattle Population (In Lac)	Affected Cattle (In Lac)
					Cultivable (Lac ha)	Sown (Lac ha)	Damaged (Lac ha)	50-74%	75-100%	less than 50%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ajmer	1139	106	1.33	4.76	3.80	0.42	91	15	0	2536	0.90	0.85	9.19	0.25
2	Banswara	1523	1505	17.90	2.86	2.25	1.35	1503	2	18	25974	10.13	10.13	13.33	13.32
3	Barmer	2712	1451	25.07	23.78	13.57	6.36	778	673	1261	72194	4.81	0.20	46.24	24.00
4	Bikaner	951	73	0.92	1.36	0.88	0.17	70	3	878	12519	0.00	0.00	1.70	1.70
5	Chittorgarh	1751	2	0.02	0.00	0.00	0.00	2	0	0	70	0.01	0.01	0.01	0.01
6	Churu	912	14	0.25	0.20	0.10	0.07	12	2	0	832	0.39	0.00	0.27	0.27
7	Dungarpur	986	986	13.90	1.82	1.30	0.81	986	0	0	2666	2.21	1.41	11.12	11.12
8	Ganganagar	453	3	0.09	0.05	0.05	0.01	3	0	12	489	0.48	0.00	0.00	0.00
9	Hanumangarh	1914	6	0.14	0.14	0.13	0.08	4	2	7	2062	0.37	0.37	0.11	0.11
10	Jaisalmer	835	790	6.08	28.41	6.30	5.41	100	690	45	37681	0.25	0.25	13.78	13.03
11	Jalore	805	89	0.83	8.67	5.98	0.53	53	36	122	8397	4.50	0.61	7.24	0.42
12	Jodhpur	1875	439	4.32	12.68	9.94	2.54	416	23	764	880026	2.85	0.00	17.78	2.89
13	Pratapgarh	1010	377	3.45	0.54	0.51	0.32	374	3	0	22344	1.54	1.52	2.87	2.87
	Total	**16866**	**5841**	**74.30**	**85.27**	**44.81**	**18.07**	**4392**	**1449**	**3107**	**1067789**	**28.44**	**15.35**	**123.64**	**69.99**

EXTENT OF SCARCITY (Rabi)
SAMVAT 2071

S.No.	District	Total Villages	No. of Affected villages (50% or more than 50%)	Population Affected (Lac)	Area of Affected Villages			Affected Villages			Value of Damaged Crop (Lac Rs.)	Land Rev. of Affected Villages (Lac Rs.)	likely Suspended of land Rev. (Lac Rs.)	Total Cattle Population (In Lac)	Affected Cattle (In Lac)
					Cultivable (Lac ha)	Sown (Lac ha)	Damaged (Lac ha)	50-74%	75-100%	less than 50%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ajmer	1139	577	17.24	4.97	2.56	1.17	463	114	502	35669	19.79	6.12	9.56	4.88
2	Alwar	2054	106	3.02	1.78	1.65	0.58	39	67	74	28678	13.43	3.86	5.03	1.97
3	Baran	1247	183	10.62	3.59	3.36	0.81	174	9	750	38309	17.54	4.96	6.44	4.00
4	Barmer	2712	236	11.02	24.41	2.41	0.57	231	5	765	29576	4.97	0.17	56.58	18.78
5	Bharatpur	1578	251	5.25	5.56	4.97	0.41	248	3	806	23479	4.88	2.38	15.27	2.51
6	Bhilwara	1898	1185	15.19	4.54	2.10	1.27	774	411	685	115240	35.11	30.47	17.83	17.08
7	Bikaner	951	31	1.49	3.13	0.97	0.22	28	3	210	189	2.32	2.23	0.32	0.00
8	Bundi	891	888	11.23	3.15	2.55	1.94	506	382	0	94564	20.87	20.87	9.65	9.65
9	Chittorgarh	1751	1422	14.28	3.41	2.44	1.21	1422	0	176	53244	26.96	25.11	13.54	9.59
10	Churu	917	123	5.32	3.45	1.02	0.13	95	28	153	12467	0.10	0.00	16.47	4.81
11	Dausa	1131	30	14.64	2.31	1.98	0.40	30	0	1022	12615	20.46	0.99	9.65	9.22
12	Dholpur	845	14	9.86	1.77	1.41	0.29	9	5	831	2585	0.00	0.50	5.70	0.27
13	Ganganagar	1949	15	0.65	1.03	0.29	0.06	11	4	102	2768	2.20	0.18	1.27	0
14	Hanumangarh	1914	4	0.20	9.12	4.63	0.04	4	0	10	563	0.44	0.08	0.22	0.02
15	Jaipur	2180	44	1.60	0.27	0.23	0.17	5	39	81	6980	3.26	3.26	5.28	1.13
16	Jaisalmer	835	75	0.71	8.28	1.93	1.11	39	36	10	6793	13.79	13.71	1.18	1.16
17	Jalore	806	1	15.96	8.67	2.47	0.52	1	0	693	10307	0.00	0	7.23	0
18	Jhalawar	1625	219	2.55	3.69	2.92	0.32	211	8	121	10270	1.70	0.62	8.71	1.42
19	Jhunjhunu	952	28	3.40	1.10	0.68	0.19	4	24	138	6715	4.79	4.14	2.39	1.55
20	Jodhpur	1876	309	18.18	12.95	3.59	1.59	268	41	1030	63043	7.17	7.17	21.90	12.77
21	Karauli	893	12	1.68	2.27	2.26	2.14	5	7	881	1782	3.16	3.16	0.64	0.64
22	Kota	953	606	9.58	2.93	2.63	1.67	370	236	295	131023	47.78	36.93	6.18	6.18
23	Nagaur	1630	324	30.96	22.54	5.07	1.16	320	4	1296	163204	35.37	11.05	14.73	9.64
24	Pali	1055	232	15.49	9.03	1.61	0.40	223	9	624	26128	41.83	19.38	6.91	5.11
25	Rajsamand	1081	327	8.16	1.20	0.33	0.12	117	210	754	1413	7.61	3.04	8.33	3.43
26	S.Madhopur	827	74	13.31	2.99	2.77	0.55	74	0	18	31151	20.73	0.64	8.27	0
27	Sirohi	506	30	8.60	1.93	0.35	0.04	22	8	213	1792	4.67	0	3.61	2.94
28	Tonk	1214	823	13.44	5.29	4.29	2.06	778	45	381	95171	23.14	20.62	8.98	8.15
29	Udaipur	1108	153	7.02	2.18	0.58	0.15	146	7	607	6029	6.11	4.39	5.99	5.17
	Rajasthan	**38518**	**8322**	**270.65**	**157.54**	**64.05**	**21.29**	**6617**	**1705**	**13228**	**1011746**	**390.18**	**226.03**	**277.86**	**142.07**

परिशिष्ट–12

Monsoon Rainfall Position (1st June to 30th Sept.2015)

S. No.	District	2013			2014			2015		
		Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation
	Ajmer Division									
1.	Ajmer	429.60	542.9	26.4	429.60	527.3	22.7	429.60	397.17	-7.55
2.	Bhilwara	580.90	667.3	14.9	580.90	614.9	5.9	580.90	406.11	-30.09
3.	Nagaur	348.50	468.9	34.5	348.50	411.0	17.9	348.50	401.37	15.17
4.	Tonk	566.00	860.5	52.0	566.00	707.9	25.1	566.00	476.80	-15.76
	Bharatpur Division									
5.	Bharatpur	557.60	562.3	0.8	577.60	439.6	-21.2	557.60	412.72	-25.98
6.	Dholpur	650.00	864.7	33.0	650.00	491.2	-24.4	650.00	396.79	-38.96
7.	Karauli	637.40	814.8	27.8	637.40	516.7	-18.9	637.40	366.39	-42.52
8.	S.Madhopur	664.00	871.6	31.3	664.00	621.8	-6.4	664.00	444.59	-33.04
	Bikaner Division									
9.	**Bikaner**	228.70	233.1	1.9	228.70	222.0	-2.9	228.70	356.98	56.09
10.	Churu	313.70	406.3	29.5	313.70	363.0	15.7	313.70	383.31	22.19
11.	Ganganagar	201.40	154.2	-23.4	201.40	259.6	28.9	201.40	280.64	39.34
12.	Hanumangarh	252.50	282.9	12.0	252.50	273.3	8.2	252.50	262.57	3.99
	Jaipur Division									
13.	Alwar	555.30	594.5	7.1	555.30	387.6	-30.2	555.30	348.45	-37.25
14.	Dausa	612.10	786.4	28.5	612.10	591.4	-3.4	612.10	315.71	-48.42
15.	Jaipur	524.60	574.0	9.4	524.60	473.6	-9.7	524.60	341.32	-34.94
16.	Jhunjhunu	410.00	459.4	12.1	410.00	401.4	-2.1	410.00	347.21	-15.31
17.	Sikar	402.50	457.0	13.5	402.50	480.5	19.4	402.50	458.50	13.91
	Jodhpur Division									
18.	Barmer	243.40	431.9	77.4	243.40	211.1	-13.3	243.40	406.59	67.05
19.	Jaisalmer	158.40	210.9	33.2	158.40	91.5	-42.2	158.40	322.03	103.30
20.	Jalore	394.20	539.0	36.7	394.20	340.6	-13.6	394.20	647.73	64.32
21.	Jodhpur	274.50	487.9	77.7	274.50	275.5	0.4	274.50	361.00	31.51
22.	Pali	446.70	535.8	19.9	446.70	505.4	13.1	446.70	526.07	11.77
23.	Sirohi	868.60	712.1	-18.0	868.60	630.6	-27.4	868.60	831.46	-4.28
	Kota Division									
24.	Baran	792.20	1535.5	93.8	792.20	1020.6	28.8	792.20	892.71	12.69
25.	Bundi	655.90	876.3	33.6	655.90	684.7	4.4	655.90	620.46	-5.40
26.	Jhalawar	855.10	1374.1	60.7	855.10	787.7	-7.9	855.10	1096.32	28.21
27.	Kota	746.30	1171.3	56.9	746.30	718.8	-3.7	746.30	775.72	3.94
	Udaipur Division									
28.	Banswara	831.80	1019.2	22.5	831.80	646.1	-22.3	831.80	673.83	-18.99
29.	Chittorgarh	709.70	926.0	30.5	709.70	786.4	10.8	709.70	584.46	-17.65
30.	Dungarpur	637.80	873.4	36.9	637.80	599.2	-6.1	637.80	671.13	5.23
31.	Pratapgarh	845.80	1183.2	39.9	845.80	706.6	-16.5	845.80	652.96	-22.80
32.	Rajsamand	506.00	646.1	27.7	506.00	531.4	5.0	506.00	527.36	4.22
33.	Udaipur	591.30	758.9	28.3	591.30	714.0	20.8	591.30	633.79	7.19
Avr. Rajasthan		**530.08**	**691.2**	**30.4**	**530.08**	**518.7**	**-2.1**	**530.08**	**505.15**	**-4.70**

District wise Drought Frequency in Rajasthan

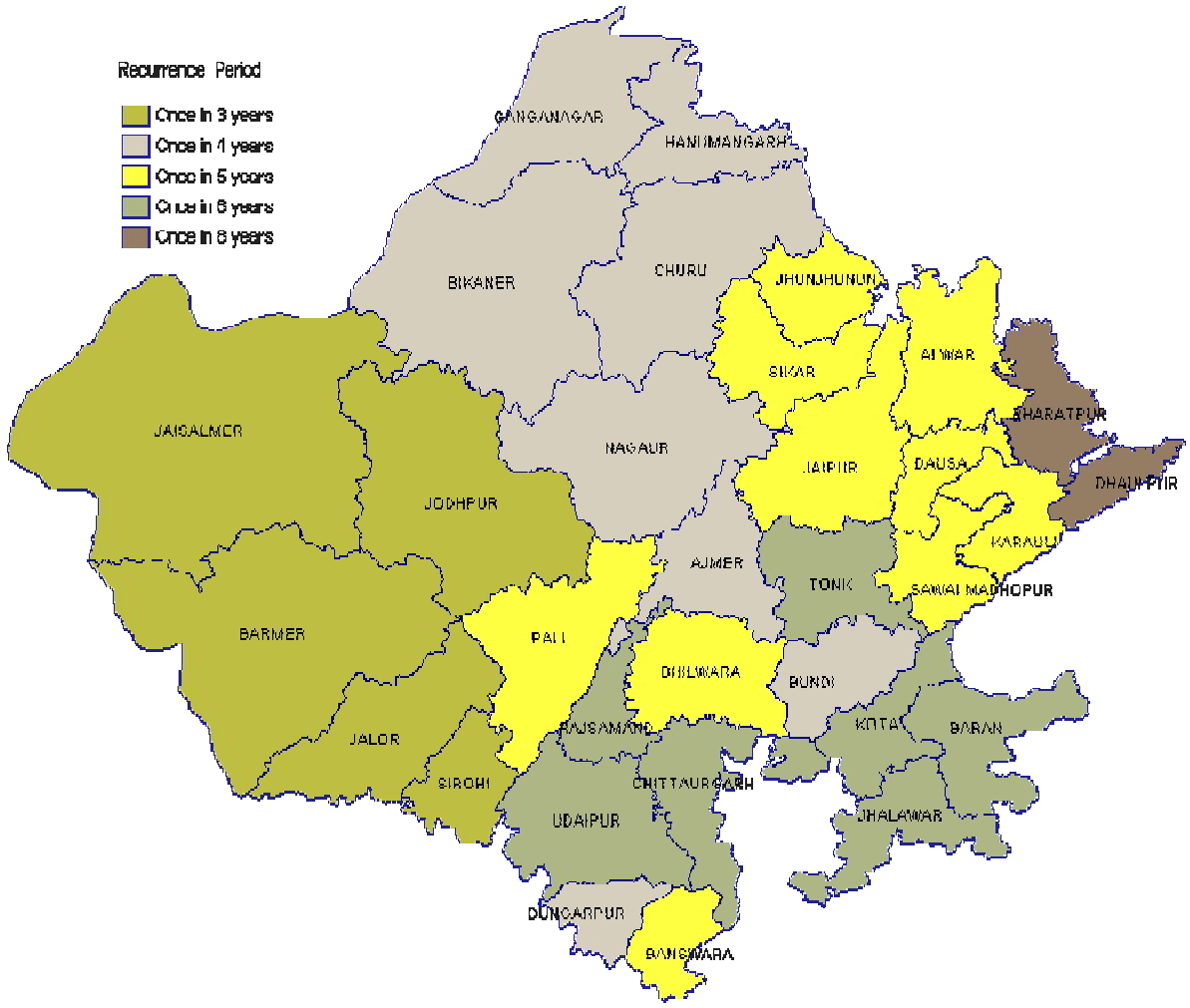

परिशिष्ट–14

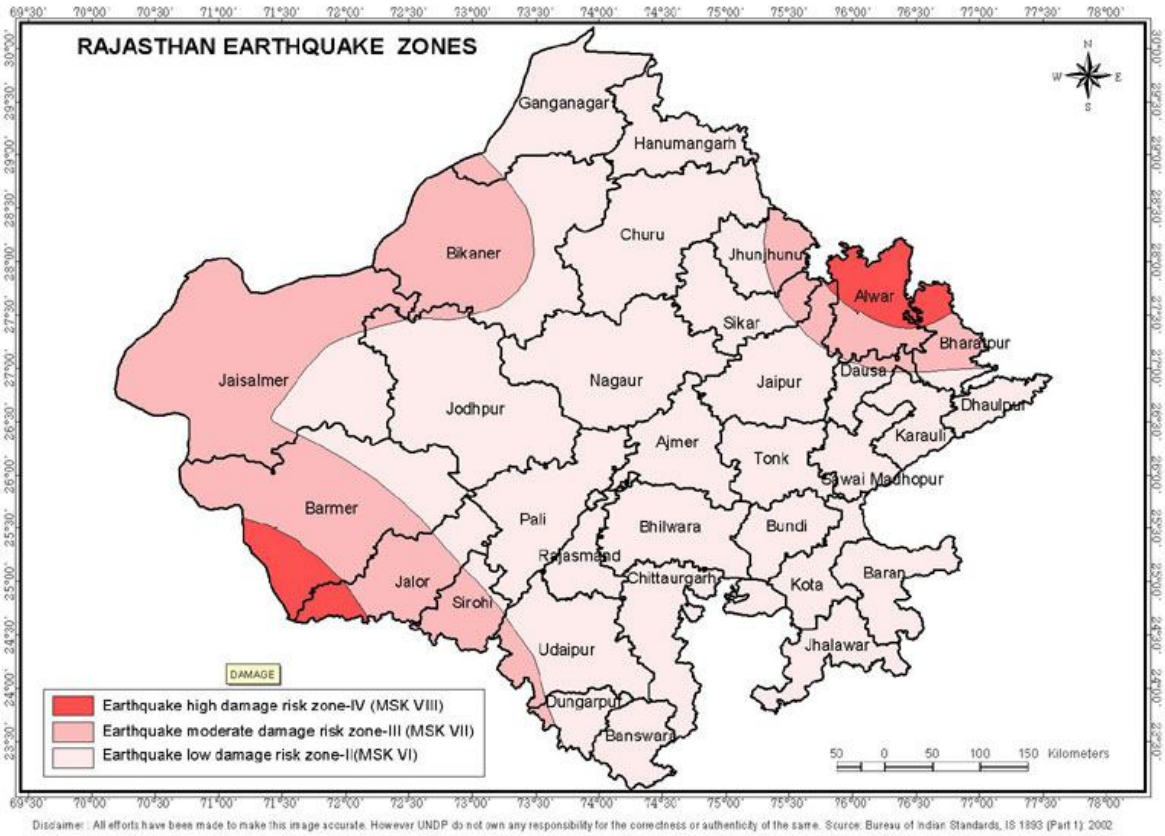

Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However UNDP do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. Source: Bureau of Indian Standards, IS 1893 (Part 1): 2002

परिशिष्ट–15

No. 32-7/2014-NDM-1
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II
Jai Singh Road, New Delhi-110001,
Dated the 8th April 2015

To

1. Chief Secretaries of all States
2. The Relief Commissioners / Secretaries, Department of Disaster Management of all States

Subject: - Items and Norms of assistance from the State Disaster Response Fund (SDRF) and the National Disaster Response Fund (NDRF) for the period 2015-2020.

Sir/Madam,

I am directed to state that based on consideration of the recommendations of Fourteenth Finance Commission (FFC) on financing of expenditure on immediate relief during natural disasters for the period 2015-2020 and the report of the Expert Group set up by this Ministry, the Government of India has revised the items and norms for assistance from SDRF/NDRF. The approved list of items and norms for assistance from SDRF/NDRF in the wake of identified natural disasters is Annexed. The revised norms will be effective from 1st April 2015. However, the farmers affected by hailstorms in different parts of the country during February/March 2015 will also be given assistance under the new norms.

2. The revised items and norms can also be downloaded from website of Disaster Management Division of Ministry of Home Affairs i.e. www.ndmindia.nic.in.

3. As the first charge on SDRF should be on a disaster of severe nature, there has been a requirement to adjust balance amount of SDRF whenever NDRF amount is released. This procedure stands revised as follows:-

> 50 % of SDRF balance, as on 31st March of the preceding financial year, will be adjusted while releasing the assistance form NDRF for the first disaster in a financial year. In case the same State faces another severe disaster during the same year, no adjustment will be made while releasing NDRF assistance.

4. A copy of the communication alongwith their enclosure is also being sent to the Accountants Generals of the States for necessary action.

5. This supersedes this Ministry's earlier letters on this subject, the last being No.32-3/ 2013-NDM-I dated the 28th November, 2013 and No. 32-3/2013 NDM-I dated 5th March 2014.

Yours Faithfully,
Sd/-
(Goutam Ghosh)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele fax : 23438123

Encl: As above
Copy for information and necessary follow up action to:-

1. Accountants General of all State Governments.
2. Comptroller & Auditor general (CAG), New Delhi.
3. Controller General of Accounts (CGA), New Delhi.
4. Resident Commissioners of all State Governments.

Copy to:-

1. Ministry of Finance, Department of Expenditure [Shri Vivek Joshi, JS (FCD)], North Block , New Delhi.
2. Ministry of Agriculture [Joint Secretary (DM)], Krishi Bhawan, New Delhi.
3. Member Secretary, National Disaster Management Authority, NDMA Bhawan, Safdurjung Enclave, New Delhi.
4. All concerned Central Ministries/Departments/Organizations.
5. PMO / Cabinet Secretariat.
6. PS to HM/PS to MOS (R)
7. Sr. PPS to Home Secretary/ Addl. Secretary (F)/ Joint Secretary (DM)/NIC.

*****

Annexure

REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM STATE DISASTER RESPONSE FUNDS (SDRF) AND NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND (NDRF)

(Period 2015-20, MHA Letter No.32-7/2014-NDM-I Dated 08th April, 2015)

Sl.No.	Items	NORMS OF ASSISTANCE
1	2	3
I	Gratuitous Relief	
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons	Rs.4.00 lakh per deceased person including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to certification regarding cause of death from appropriate authority.
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s)	Rs. 59,100/- per person, when the disability is between 40% and 60% Rs. 2.00 Lakh per person, when the disability is more than 60%. Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding extent and cause of disability.
	c) Grievous injury requiring hospitalization	Rs.12,700/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs.4,300/- per person requiring hospitalization for less than a week.
	d) Clothing and utensils/house-hold goods for families whose houses have been washed away/ fully damaged/ severely inundated for more than two day due to a natural calamity.	Rs.1,800/- per family, for loss of clothing Rs.2,000/- per family, for loss of utensils/household goods.
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	Rs.60/- per adult and Rs.45/- per child, not housed in relief camps. State Govt. will certify that identified beneficiaries are not housed in relief camps. Further State Government will provide the basis and process for arriving at such beneficiaries district-wise. Period for providing gratuitous relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period of assistance will upto to 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance, if required, and subsequently upto 90 days in case of drought/pest attack. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.
2.	SEARCH & RESCUE OPERATIONS	
	(a) Cost of search and rescue measures/evacuation of people affected/likely to be affected	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). - By the time the Central Team visits the affected area, these activities are already over. Therefore, the State Level Committee and the Central Team can recommend actual/near-actual costs.

	(b) Hiring of boats for carrying immediate relief and saving lives.	As per actual cost incurred, assessed by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF). The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring boats and essential equipment required for rescuing stranded people and thereby saving human lives during a notified natural calamity.
3	RELIEF MEASURES	
	a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected/evacuated and sheltered in relief camps.	As per assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF), for a period up to 30 days. The SEC would need to specify the number of camps, their duration and the number of persons in camps. In case of continuation of a calamity like drought, or widespread devastation caused by earthquake or flood etc., this period may be extended to 60 days, and upto 90 days in case of severe drought. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Medical care may be provided from National Rural Health Mission (NRHM)
	b) Air dropping of essential supplies	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) - The quantum of assistance will be limited to actual amount raised in the bills by the Ministry of Defence for airdropping of essential supplies and rescue operations only.
	c) Provision of emergency supply of drinking water in rural areas and urban areas	As per actual cost, based on assessment of need by SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF), up to 30 days and may be extended upto 90 days in case of drought. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit subject to that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year.
4	CLEARANCE OF AFFECTED AREAS	
	a) Clearance of debris in public areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team for assistance to be provided under NDRF.
	b) Draining off flood water in affected areas	As per actual cost within 30 days from the date of start of the work based on assessment of need by SEC for the assistance to be provided under SDRF and as per assessment of the Central team (in case of NDRF).
	c) Disposal of dead bodies/Carcases	As per actual, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF)

5	AGRICULTURE	
(i)	Assistance farmers having landholding upto 2 ha.	
A	Assistance for land and other loss.	
	a) De-silting of agricultural land (where thickness of sand/silt deposit is more than 3", to be certified by the competent authority of the State Government)	Rs.12,200/- per hectare for each item (Subject to the condition that no other assistance/ subsidy has been availed of by/ is eligible to the beneficiary under any other Government Scheme)
	b) Removal of debris on agricultural land in hilly areas	
	c) De-silting/ Restoration/ Repair of fish farms	
	d) Loss of substantial portion of land caused by landslide, avalanche, change of course of rivers.	Rs.37,500/- per hectare to only those small and marginal farmers whose ownership of the land is legitimate as per the revenue records.
B	Input subsidy (where crop loss is 33% and above)	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	Rs.6,800/- per ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs.13,500/- per ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs. 1000 and restricted to sown areas.
	b) Perennial crops	Rs.18,000/- ha. for all types of perennial crops subject to minimum assistance not less than Rs.2000/- and restricted to sown areas.
	c) Sericulture	Rs.4,800/- per ha. for Eri, Mulberry, Tussar Rs.6,000/- per ha. for Muga.
(ii)	Input subsidy to farmers having more than 2 ha. of landholding	Rs.6,800/- per hectare in rainfed areas and restricted to sown areas. Rs.13,500/- per hectare for areas under assured irrigation and restricted to sown areas. Rs. 18,000/- per hectare for all types of perennial crops and restricted to sown areas. Assistance may be provided where crop loss is 33% and above, subject to a ceiling of 2 ha. per farmer.
6	ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS	
	i) Replacement of milch animals, draught animals or animals used for haulage	*Milch animals* - Rs.30,000/- Buffalo/cow/camel/yak /Mithun etc. Rs.3,000/- Sheep/Goat/Pig *Draught animals* - Rs.25,000/- Camel/horse/bullock ,etc. Rs.16,000/-Calf/Donkey/Pony/Mule - The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and will be subject to a ceiling of 3 large milch animals or 30 small milch animals or 3 large draught animals or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. (The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government)

		Poultry:- Poultry @ 50/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs.5000/- per beneficiary household. The death of the poultry birds should be on account of a natural calamity. Note :- Relief under these norms is not eligible if the assistance is available from any other Government Scheme, e.g. loss of birds due to Avian Influenza or any other diseases for which the Department of Animal Husbandry has a separate scheme for compensating the poultry owners.
	ii) Provision of fodder/feed concentrate including water supply and medicines in cattle camps	Large animals - Rs. 70/- per day Small animals - Rs.35/- per day Period for providing relief will be as per assessment of the State Executive Committee (SEC) and the Central Team (in case of NDRF). The default period for assistance will be upto 30 days, which may be extended upto 60 days in the first instance and in case of severe drought up to 90 days. Depending on the ground situation, the State Executive Committee can extend the time period beyond the prescribed limit, subject to the stipulation that expenditure on this account should not exceed 25% of SDRF allocation for the year. Based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team, (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census and subject to the certificate by the competent authority about the requirement of medicine and vaccine being calamity related.
	iii) Transport of fodder to cattle outside cattle camps	As per actual cost of transport, based on assessment of need by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) consistent with estimates of cattle as per Livestock Census.
7	FISHERY	
	i) Assistance to Fisherman for repair / replacement of boats, nets - damaged or lost -- Boat -- Dugout-Canoe -- Catamaran -- net (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme).	Rs. 4,100/- for repair of partially damaged boats only Rs.2,100/- for repair of partially damaged net Rs.9,600/- for replacement of fully damaged boats Rs.2,600/- for replacement of fully damaged net
	ii) Input subsidy for fish seed farm	Rs.8, 200 per hectare. (This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Department of Animal; Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture).

8	HANDICRAFTS/ HANDLOOM – ASSISTANCE TO ARTISANS	
	i) For replacement of damaged tools/ equipment	Rs. 4,100 per artisan for equipments. - Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	Rs. 4,100 per artisan for raw material. - Subject to certification by competent authority designated by the State Government about loss and its replacement.
9	HOUSING	
	a) Fully damaged/ destroyed houses	
	i) Pucca House	Rs. 95,100/- per house, in plain areas. Rs. 1,01,900/- per house, in hilly areas including Integrated Action Plan (IAP) districts.
	ii) Kutcha House	
	b) Severely damaged houses	
	i) Pucca House	
	ii) Kutcha House	
	(c) Partially Damaged Houses -	
	(i) Pucca (other than huts) where the damage is at least 15%	Rs.5,200/- per house
	(ii) Kutcha (other than huts) where the damage is at least 15%	Rs3,200/- per house
	d) Damaged/destroyed huts:	Rs. 4,100/- per hut, (Hut means temporary make shift unit, inferior to kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc, traditionally recognized as hut by the State/District authorities.) Note:- The damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government
	d) Cattle shed attached with house	Rs. 2,100/- per shed
10	INFRASTRUCTURE	
	Repair/restoration (of immediate nature) of damaged infrastructure : (1) Roads & Bridges (2) Drinking Water Supply Works (3) Irrigation (4)Power (only limited to immediate restoration of electricity supply in the affected areas), (5) Schools, (6) Primary Health Centers (7) Community assets owned by Panchayat Sectors such as Telecommunication and Power (except immediate restoration of power supply), which generate their own revenues, and also undertake immediate repair/ restoration works from their own funds/ resources, are excluded.	Activities of immediate nature : Illustrative lists of activities which may be considered as works of an immediate nature are given in the enclosed Appendix. Assessment of requirements : Based on assessment of need, as per States' costs/rates/ schedules for repair, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF) - As regards repair of roads, due consideration shall be given to Norms for Maintenance of Roads in India, 2001, as amended from time to time, for repairs of roads affected by heavy rains/floods, cyclone, landslide, sand dunes, etc. to restore traffic.

		For reference these norms are • Normal and Urban areas: upto 15% of the total of Ordinary Repair (OR) and Periodical Repair (PR) • Hills : upto 20% of total of OR and PR - In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR rate is not available, then assistance will be provided @ Rs 1 lakh/km for State Highway and Major District Road and @ Rs. 0.60 lakh/km for rural roads. The condition of "State shall first use its provision under the budget for regular maintenance and repair" will no longer be required, in view of the difficulties in monitoring such stipulation, though it is a desirable goal for all the States. - In case of repairs of bridges and Irrigation works, assistance will be given as per the schedule of rates notified by the concerned States. Assistance for micro irrigation scheme will be provided @ Rs. 1.5 lakh per damaged scheme. Assistance for restoration of damaged medium and large irrigation projects will also be given for the imbankment portions, on par with the case of similar rural roads, subject to the stipulation that no duplication would be done with any ongoing schemes. - Regarding repairs of damaged drinking water schemes, the eligible damaged drinking water structures will be eligible for assistance @ Rs. 1.5 lakh / damaged structure. - Regarding repair of damaged primary and secondary schools, primary health centers, Aanganwadi and community assets owned by the Panchayats, assistance will be given @ Rs. 2 lakh/damaged structure. - Regarding repair of damaged power sector, assistance will be given to damaged conductors, poles and transformers up to the level of 11 kV. The rate of assistance will be @ Rs. 4000/poles, Rs 0.50 lakh per km of damaged conductor and Rs. 1.00 lakh per damaged distribution transformer.
11	Procurement of essential search, rescue and evacuation equipments including communication equipments, etc. for response to disaster.	- Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The total expenditure on this item should not exceed 10% of the annual allocation of the SDRF.
12	Capacity Building	- Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not from NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The total expenditure on this item should not exceed 5% of the annual allocation of the SDRF.

13	State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRDF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF.	- Expenditure is to be incurred from SDRF only (and not form NDRF), as assessed by the State Executive Committee (SEC). - The norm for various items will be the same as applicable to other notified natural disasters, as listed above, or - In these cases, the scale of relief assistance against each item for 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF. - The flexibility is to be applicable only after the State has formally listed the disasters for inclusion and notified transparent norms and guidelines with a clear procedure for identifications of the beneficiaries for disaster relief for such local disasters with the approval of SEC.

Note:- (i) The State Government are to take utmost care and ensure that all individual beneficiary oriented assistance is necessary mandatory disbursed through the bank account (viz; Jan Dhan Yojna etc.) of the beneficiary.

(ii) The scale of relief assistance against each item for all disasters including 'local disaster' should not exceed the norms of SDRF/NDRF. Any amount spent by the State for such disasters over and above the ceiling would be borne out of the resources of the State Government and not from SDRF

APPENDIX
(Item No.10)

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :
   i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
   ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
   iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake - structure, approach gantries/jetties.
2. Roads :
   i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
   ii) Repair of breached culverts.
   iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
   iv) Temporary repair of approaches to bridges/ embankments of bridges, repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.
3. Irrigation :
   i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
   ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
   iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.
   iv) Repair of embankments of minor, medium and major irrigation projects.
4. Health :
   Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/community Health Centers.
5. Community assets of Panchayat
   a) Repair of village internal roads.
   b) Removal of debris from drainage/sewerage lines
   c) Repair of internal water supply lines
   d) Repair of street lights
   e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghar, community halls, anganwadi, etc.
6. Power: Poles/conductors and transformers up to 11kv.

7. The assistance will be considered as per the merit towards the following activities :

	Items/Particulars	Norms of assistance will be adopted for immediate repair
i)	Damaged primary school building Higher secondary/ middle/ college and other educational institutions buildings	Up to Rs.1.50 lakh/ unit Not covered
ii)	Primary Health Centre	Upto Rs.1.50 lakh/ unit
iii)	Electric poles and wires etc	Normative cost (Upto Rs.4000 per pole and Rs.0.50 lakh per km)
iv)	Panchayat Ghar/ Anganwadi/ Mahila Mandal/ Yuva Kendra/ Community Hall	Upto Rs.2.00 lakh/ unit
v)	State Highways/ Major District road	Rs. 1.00 lakh/ km*
vi)	Rural road/ bridge	Rs. 0.60 lakh/ km*
vii)	Drinking water scheme	Upto Rs.1.50 lakh/ unit
viii)	Irrigation Sector : Minor irrigation schemes/ Canal Major irrigation scheme Flood control and anti Erosion Protection work	 Upto Rs.1.50 lakh/ scheme Not covered Not covered
ix	Hydro Power Project/ HT Distribution systems/ Transformers and sub stations	Not covered
x)	High Tension Lines (above 11 kv)	Not covered
xi)	State Govt. Buildings viz. departmental/ office building, departmental/ residential quarters, religious structures, Patwarkhana, court premises, play ground, forest bungalow property and animal/ bird sanctuary etc.	Not covered
xii)	Long terms/ Permanent Restoration works incentive	Not covered
xiii)	Any new work of long term nature	Not covered
xiv)	Distribution of commodities	Not covered (However, there is a provision for assistance as GR to families in dire need of assistance after a disasters)
xv)	Procurement if equipment/ machineries under NDRF	Not covered
xvi)	National Highways	Not covered (Since GOI born entire expenditure towards restoration works activities)
xvii)	Fodder seed to augment fodder production	Not covered

*If OR & PR rules are not provided by the State.